ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
फलों को पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किसी को जहर देने के समान

रविवारीय, 08 - 14 मार्च 2020 वर्ष- एक, अंक-31, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

रंगों और उमंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से आप सभी प्रिय पाठकों को बहुत सारी शुभकामनायें

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

सभी महिलाओं को नमन करता हूं, आईये इनका सम्मान करें:हेमन्त सोरेन

रांची :मुख्यमंत्री आवास, रांची मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखण्ड की महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा मैं सभी महिलाओं को नमन करता हूं। नारी के सहयोग से शिक्षा, सुरक्षा, सभ्य एवं प्रगतिशील समाज सुनिश्चित हो सकता है। इनके अदम्य साहस एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों से सशक्त भारत के निर्माण में भूमिका रही है। इन उपलब्धियों और अदम्य साहस ने हर क्षण हमारे हृदय को गौरवान्वित किया है। नारी शक्ति को पुनः मेरा नमन। आईये इनका सम्मान करें।

रेलवे के महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने कार्य अनुभव पर चर्चा की

रांची :8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तथा इस अवसर पर दिनांक 1 मार्च 2020 से 10 मार्च 2020 तक रांची रेल मंडल में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत 3 मार्च 2020 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागृह में मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ की मुख्य उपस्थिति में मंडल पर कार्यरत विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो यात्रियों / व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आकर अपना कार्य निष्पादित करती हैं, ने अपने कार्य अनुभव पर चर्चा की। इस चर्चा सत्र में परिचालन, वाणिज्य, सिग्नल एवं दूरसंचार, कार्मिक, रेल सुरक्षा बल, यांत्रिक, चिकित्सा, विद्युत, इंजीनियरिंग, भंडार विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने अपने कार्य अनुभव बताएं ।

डैम तालाबों पर दिखावा नहीं सख्त एक्शन ले सरकार

मुख्य संवाददाता

रांचीः राज्य में डैमों तालाबों को अतिक्रमण और प्रदूषण से रोकने और उनके संरक्षण पर बातें तो खूब होती रही हैं, पर ये अफसोस की बात है कि इन जीवनदायी जलस्त्रोतों को बचाने के लिये सरकारों ने कभी ठोस कदम नहीं उठाये हैं। रांची के कांके डैम और बड़ा तालाब के प्रदूषण, अतिक्रमण पर खबरें तो खूब प्रकाशित हुईं पर सरकार ने ठोस कार्रवाई कभी नहीं की।

पिछली सरकार में रांची में राजधानी के सभी तालाबों के जीणोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ था। लेकिन इसका हश्र ये हुआ कि सारे तालाबों को बर्बाद कर दिया गया। असल में ये सौंदर्यीकरण के नाम पर मोटे ठेके का काम हुआ था। वहीं शहर के बीच स्थित कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त कराने और इसके कैचमेंट में बने अवैध मकानों को हटाने के प्रति सरकारें कभी भी गंभीर नहीं रही। उल्टे तकरीबन छह सात साल पहले ग्रीन लैंड और कैचमेंट में बने कुछेक मकानों को तोड़ा गया था आज उससे ज्यादा मजबूत और बड़े मकान इसके कुछ हिस्सों के कैचमेंट में बना लिये गये हैं। कांके डैम का निर्माण साठ के दशक में ही कराया गया था।

पहले कांके डैम से जुड़ी नदी को बचायें

ग्रीन रिवोल्ट ने 15 अगस्त 2019 के अपने पहले अंक में ही कांके डैम के एकमात्र जलस्त्रोत वाली नदी के अतिक्रमण और उसके विलुप्ति पर खबर प्रकाशित की थी। यह एक दुखद बात है कि सरकार के अलावा आम जन भी कभी इन मुद्दों को गंभीरता से नही लेते। हम अपने पाटकों को बताना चाहेंगे कि कांके डैम में रातू रोड के पंडरा पुल के नीचे से बहने वाली नदी आकर मिल जाती है और बरसात में यही एकमात्र नदी है जो डैम के लिये पानी लेकर आती है जो एकत्र होता है। इस नदी की विलुप्ति पर आज तक किसी मीडिया हाउस ने ध्यान नहीं दिया। हकीकत में कभी सदानीरा रहने वाली यह नदी अब पंडरा के पास की बस्तियों में पुरी तरह से बांध कर खत्म कर दी गयी है और इस पर मकान बना लिये गये हैं। पहले इसी नदी में पंचशील नगर से लुप्त हुई नदी आकर मिल जाती थी। अगर यह नदी अपने मूल स्वरूप में आ जाती है तो कांके डैम के लिये जीवनदायिनी बन जायेगी।

सबकी नजर सिर्फ कांके रोड की ओर से अतिक्रमण पर

जब भी कांके डैम के अतिक्रमण पर खबरें बनती हैं या सरकार की ओर से कोई मुआयना करने जाता है तो वह कांके रोड के कॉलोनियों की ओर देख आता है। ये हकीकत भी है कि उस ओर विशाल आवासिय मकान बना लिये गये हैं, लेकिन इसके अलावा डैम के पश्चिमी सिरे की ओर नवासोसो की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।यहां डैम का इकोस्सिटम आज भी समृद्ध है और इधर ही पंडरा से आकर नदी डैम में मिल जाती है। चुंकि इधर लोगों की नजर नहीं जाती इस कारण कैचमेंट में अतिक्रमण कर मकान भी बना लिये गये है।

पंजाब हरियाणा से सीख सकता है झारखंड

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुखना झील के कैचमेंट एरिया में मौजूद सभी व्यावसायिक व आवासीय निर्माण तीन माह के भीतर हटाने के निर्देश निश्चित रूप से प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बदलावकारी कदम है। निःसंदेह सुखना लेक न केवल चंडीगढ़ की पहचान से जुड़ी है, बल्कि शहर की आबोहवा व तापमान को भी प्रभावित करती है। यदि सुखना सूखी तो चंडीगढ़ महज पत्थरों का शहर बनकर रह जायेगा। वहीं हरियाणा व पंजाब सरकारों पर सौ-सौ करोड़ का जुर्माना लगाना एक नजीर बनेगी कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को प्रश्रय न मिले।यहां उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को नजरअंदाज करके क्षेत्र में निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रहने दिया। जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस एच.एस. सिद्धू की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जो संवेदनशीलता दिखायी है, उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। अदालत ने सुखना लेक संरक्षण के लिये दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए झील को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। अदालत ने समाज व प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें अभिभावक की संज्ञा दी। वहीं अदालत ने धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए सृष्टि में पंचमहाभूत तत्वों के महत्व को भी रेखांकित किया, जिनसे हमारा जीवन भी चलता है। दरअसल, लगातार बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप व निर्माण कार्यों के चलते सुखना लेक का दायरा सिमटता जा रहा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को झील के एक किलोमीटर के दायरे को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने को कहा है। चिंता की बात है कि सुखना लेक का दायरा ढाई किलोमीटर से सिमटकर महज डेढ़ किलोमीटर में सिमट गया है।

दरअसल, सुखना कैचमेंट एरिया में कई वीआईपी बस्तियों के अलावा चंडीगढ़ का कैंबवाला, खुड्डा अलीशेर व किशनगढ़, पंजाब का कांसल और हरियाणा का सकेतड़ी गांव आते हैं। अदालत ने यह भी चेताया कि सुखना लेक में सीवरेज का गंदा पानी न पहुंचे। निःसंदेह अदालत के आदेश की पालना के तहत तीन महीने में कैचमेंट एरिया के व्यावसायिक व रिहायशी निर्माण गिराने होंगे। ऐसे में न्यायपूर्ण ढंग से पुनर्वास करना शासन-प्रशासन की जवाबदेही है। अदालत ने कहा भी है कि जिन लोगों के बिल्डिंग प्लान स्वीकृत हैं, उन्हें 25 लाख का मुआवजा दिया जाये। साथ ही उन्हें चंडीगढ़ के आसपास वैकल्पिक स्थान भी मुहैया कराया जाये। निःसंदेह, यहां चूक प्रशासन की तरफ से रही है कि अवैध निर्माण कार्य को प्रश्रय दिया गया। तभी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना कैचमेंट इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी रहने में जिम्मेदारी तय करने के लिये पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि चार सप्ताह के भीतर कमेटी गठित कर ली जाये। साथ ही अगले तीन महीने में जवाबदेही तय करके बताया जाये कि निर्माण किसकी अनुमति से हुआ है।

कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकारों पर सौ-सौ करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास तीन माह के भीतर जमा करानी होगी। इस राशि का उपयोग सुखना झील को संवारकर मूल स्वरूप में लाने के कार्य में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इससे पहले सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के निकट बनने वाले टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट को बीते वर्ष रद्द कर दिया था। इस बहुमंजिला हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चंडीगढ़ प्रशासन ने आपत्ति जतायी थी कि कैचमेंट एरिया में प्रोजेक्ट बनने का सीधा प्रभाव झील तथा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी पर पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में पंजाब के विधायकों को फ्लैट मिलने थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। निःसंदेह इस इलाके में जहां आम लोगों ने मनाही के बावजूद निर्माण किये हैं, वहीं क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों तथा बड़े नौकरशाहों के आलीशन भवनों व फार्म हाऊसों के निर्माण को भी जांच के दायरे में लाने की जरूरत है।

राज्यपाल ने किया रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची का उद्घाटन

संवाददाता

रांची :रांची विश्वविद्यालय का बहुप्रतीक्षित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची रविवार 8 मार्च को आन एयर हो गया। राज्यपाल ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया और सबसे पहले विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रसारित हुआ। विश्वविद्यालय अपने खुद के रेडियो प्रसारण रेडियो खांची के लिये लंबे समय से प्रयासरत था। और अंतत यह वीसी डॉ. रमेश शरण , प्रोवीसी डॉ. कामिनी कुमार, जूलॉजी के प्राध्यापक आनंद ठाकुर के प्रयासों से कार्यरत हो गया।

इस अवसर पर वीसी डॉ. रमेश कुमार पांडेय ने उपस्थित सभी छात्रों , प्राध्यापकों और मीडियाकर्मियों को भी बधाई दी और कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आज ही हम रेडियो खांची को ऑन एयर भी कर रहे हैं जो हमारे लिये गर्व की बात है। यह आपका रेडियो स्टेशन है। अब यहां से विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक सूचनायें एडमिशन, रजिस्ट्रेशन या अन्य खबरें रेडियो खांची पर ही सभी छात्रों अभिभावकों को प्राप्त हो जाया करेंगी। मौके पर प्रोवीसी , सीसीडीसी, रजिस्ट्रार , प्राध्यापक डॉ. आनंद ठाकुर, सुशील अंकन तथा बहुत सारे छात्र उपस्थित थे।

राज्यवासियों को पवित्र त्यौहार होली की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं :मुख्यमंत्री

संवाददाता

पवित्र त्यौहार होली सामाजिक समरसता का प्रतीक

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड की समस्त जनता सहित देशवासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पवित्र त्यौहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों का नया-नया रंग लेकर आए यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश और समाज में पवित्र त्यौहार होली सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। होली के दिन लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि होली के अवसर पर राज्यवासियों में आपसी भाईचारा, प्रेम-सौहार्द बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से होली त्यौहार पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की समस्त जनता साथ मिलकर रंग रूप, गरीबी-अमीरी, जाति-धर्म से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें, होली के अवसर पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज नया विधानसभा में आयोजित होली मिलन समारोह में कहीं।

मुख्यमंत्री ने जमकर उड़ाए अबीर-गुलाल इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, सभी मंत्री सहित

सभी विधायकों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री सहित विधायकों ने ढ़ोलक और झाल बजाकर होली का गाना गाया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी मंत्री एवं विधायकों को जमकर अबीर-गुलाल लगाया और होली की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी।

रेलवे ने महिला कांस्टेबल को पुरस्कृत किया

रांची संवाददाता : दिनांक 03.03.2020 को ट्रेन संख्या 68037 रांची - टोरी मेमू पैसेंजर में लोहरदगा स्टेशन पर एक महिला यात्री के गले से सोने का चेन छीनने वाले अपराधी को बड़े सतर्कता और तत्परता के साथ महिला कॉन्स्टेबल श्रीमती मंजू जायसवाल ने पकड़ा इस साहसिक कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ महिला कॉन्स्टेबल को पुरस्कृत किया और बधाई दी । साथ ही इस तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

इस अवसर पर वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जन संपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर, मण्डल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव, सहायक सुरक्षा एवं आयुक्त ए के पांडे उपस्थित थे ।

द रांची प्रेस क्लब ने महिला पत्रकारों को सम्मानित किया

रांची संवददाताः द रांची प्रेस क्लब ने 8 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची के महिला पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित इस बहुत ही सफल आयोजन में बहुत बड़ी संख्या में महिला पत्रकारों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को पद्मश्री बलबीर दत्त, संजय मिश्र, वीपी शरण, वासवी कीरो , हरिनारायण सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष रोजश सिंह व अन्य गण्य मान्य पत्रकारों ने संबोधित किया और महिला पत्रकारों की सराहना की। कार्यक्रम में रांची की विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्यरत महिला पत्रकारों ने अपने विचार रखे। पूनम केरकेट्टा, वासवी कीरो, छंदोश्री ठाकुर सभी ने अपने विचार सुनाये। शाहरोज कमर ने अपनी कविता भी लोगों को सुनाया आयोजन का संचालन महिला पत्रकार और प्रेस क्लब में कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका मिश्रा ने किया।

सुखना झील से जुड़े सुख समझें

संवाददाता

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुखना झील के कैचमेंट एरिया में मौजूद सभी व्यावसायिक व आवासीय निर्माण तीन माह के भीतर हटाने के निर्देश निश्चित रूप से प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बदलावकारी कदम है। निःसंदेह सुखना लेक न केवल चंडीगढ़ की पहचान से जुड़ी है, बल्कि शहर की आबोहवा व तापमान को भी प्रभावित करती है। यदि सुखना सूखी तो चंडीगढ़ महज पत्थरों का शहर बनकर रह जायेगा। वहीं हरियाणा व पंजाब सरकारों पर सौ-सौ करोड़ का जुर्माना लगाना एक नजीर बनेगी कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को प्रश्रय न मिले। यहां उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को नजरअंदाज करके क्षेत्र में निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रहने दिया। जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस एच.एस. सिद्धू की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जो संवेदनशीलता दिखायी है, उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। अदालत ने सुखना लेक संरक्षण के लिये दायर सात याचिकाओं पर विचार करते हुए झील को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। अदालत ने समाज व प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें अभिभावक की संज्ञा दी। वहीं अदालत ने धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए सृष्टि में पंचमहाभूत तत्वों के महत्व को भी रेखांकित किया, जिनसे हमारा जीवन भी चलता है। दरअसल, लगातार बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप व निर्माण कार्यों के चलते सुखना लेक का दायरा सिमटता जा रहा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को झील के एक किलोमीटर के दायरे को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने को कहा है। चिंता की बात है कि सुखना लेक का दायरा ढाई किलोमीटर से सिमटकर महज डेढ़ किलोमीटर में सिमट गया है।

दरअसल, सुखना कैचमेंट एरिया में कई वीआईपी बस्तियों के अलावा चंडीगढ़ का कैंबवाला, खुड्डा अलीशेर व किशनगढ़, पंजाब का कांसल और हरियाणा का सकेतड़ी गांव आते हैं। अदालत ने यह भी चेताया कि सुखना लेक में सीवरेज का गंदा पानी न पहुंचे। निःसंदेह अदालत के आदेश की पालना के तहत तीन महीने में कैचमेंट एरिया के व्यावसायिक व रिहायशी निर्माण गिराने होंगे। ऐसे में न्यायपूर्ण ढंग से पुनर्वास करना शासन-प्रशासन की जवाबदेही है। अदालत ने कहा भी है कि जिन लोगों के बिल्डिंग प्लान स्वीकृत हैं, उन्हें 25 लाख का मुआवजा दिया जाये। साथ ही उन्हें चंडीगढ़ के आसपास वैकल्पिक स्थान भी मुहैया कराया जाये। निःसंदेह, यहां चूक प्रशासन की तरफ से रही है कि अवैध निर्माण कार्य को प्रश्रय दिया गया। तभी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना कैचमेंट इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी रहने में जिम्मेदारी तय करने के लिये पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि चार सप्ताह के भीतर कमेटी गठित कर ली जाये। साथ ही अगले तीन महीने में जवाबदेही तय करके बताया जाये कि निर्माण किसकी अनुमति से हुआ है।

कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकारों पर सौ-सौ करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास तीन माह के भीतर जमा करानी होगी। इस राशि का उपयोग सुखना झील को संवारकर मूल स्वरूप में लाने के कार्य में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इससे पहले सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के निकट बनने वाले टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट को बीते वर्ष रद्द कर दिया था। इस बहुमंजिला हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चंडीगढ़ प्रशासन ने आपत्ति जतायी थी कि कैचमेंट एरिया में प्रोजेक्ट बनने का सीधा प्रभाव झील तथा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी पर पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में पंजाब के विधायकों को फ्लैट मिलने थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। निःसंदेह इस इलाके में जहां आम लोगों ने मनाही के बावजूद निर्माण किये हैं, वहीं क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों तथा बड़े नौकरशाहों के आलीशन भवनों व फार्म हाऊसों के निर्माण को भी जांच के दायरे में लाने की जरूरत है।

सराहनीय निर्णय

झारखंड सरकार ने रांची में एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क चौड़ीकरण में पहले से स्थित वृक्षों को न काटने का फैसला लिया है। भले हम विकास के लिये पेड़ों की कटाई को आवश्यक बता कर हरियाली को नष्ट करने की कितनी भी दलीलें दें, पर अंततः यह हमारे लिये आत्मघाती ही होता है। हाल के कुछ सालों में देश भर में लाखों वृक्षों को सड़क या अन्य निर्माण के लिये काटा गया है और इसे जरूरी भी बताया गया है लेकिन इसकी भरपाई हम नहीं करते। एक बात याद रखनी होगी कि एक पहले से उपलब्ध जंगल या हरियाली वाले क्षेत्र को हम काट कर खत्म तो कर देते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसके एवज में लगाये गये वृक्ष उतनी हरियालीयुक्त इलाके का निर्माण फिर से कर पायेंगे? इसलिये सरकार का वन एवं पर्यावरण विभाग की ये कोशिश होनी चाहिये कि किसी भी सूरत में वर्षों में तैयार हुये जंगलों को न काटा जाये। बल्कि इसके लिये कोई वैकल्पिक उपाय खोजा जाये। हम मनुष्यों की इच्छायें और जरूरते तो अनंत हैं और इसकी पुर्ति के लिये तो हम सदैव ही जंगलों को उजाड़ते रहेंगे।

इस बीच एक मायूस करने वाली खबर है कि बेंगलुरू में सड़क के चौड़ीकरण के लिए KRDCL कंपनी 8561 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव दिया है। बानरघट्टा, सरजापुर, मंडूर, अनेकाल और व्हाइटफील्ड के बीच मौजूदा दो-लेन और चार-लेन की सड़कों को चार-लेन और छह-लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इनमें से कुछ पेड़ 80 साल से अधिक पुराने हैं और इनमें पीपल, बरगद, इमली और अन्य प्रजातियां शामिल हैं। बेंगलुरु के नागरिकों का एक समूह KRDCL के प्रबंध निदेशक, बीएस शिवकुमार के साथ 14 फरवरी 2020 को वार्ता में शामिल हुआ जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है।10,000 से अधिक नागरिकों का एक आंदोलन इन पेड़ों की कटाई के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये आंदोलन यह भी जता रहा है कि वहां का आम आदमी भी पेड़ो और जंगलों की कटाई से दुखित है।

मुंबई के आड़े जंगलों की कटाई हो , हजारीबाग के बरही में सड़क चौड़ीकरण में हजारों पेड़ों की कटाई रांची टाटा सड़क निर्माण में विशाल पुराने वृक्षों की कटाई और उनका गायब होना ये सभी पर्यावरण को भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी भरपाई भी सिर्फ वृक्षारोपण कर देने भर से ही नहीं हो जाती। दशकों में तैयार होने वाले किसी हरे भरे जंगल को हम भले घंटों में काट कर खत्म तो कर देते हैं लेकिन उस हरियाली को वापस पाने में फिर से दशकों लगते हैं। ऐसे में रांची एयरपोर्ट रोड चौड़ीकरण में पेड़ों को न काटने का सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है।

मौसम की भविष्यवाणी और अरबों का व्यापार

मौसम की सटीक भविष्यवाणी के पीछे अकूत पैसा छुपा हुआ है। कई संस्थाएं आगामी 10-15 दिन के मौसम और तामपान की जानकारी मुहैया कराती हैं। अब एक अमेरिकी कंपनी का दावा है कि वह आगामी 40 दिन के मौसम की सटीक जानकारी दे सकती है।

मौसम का व्यापार पर क्या असर पड़ता है, पहली नजर में यह सवाल अटपटा सा लगता है। लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि तूफान, बारिश और बाढ़ जैसे हालात से व्यापार जगत को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। अकेले अमेरिका में हर साल मौसम की वजह से व्यापार जगत के 485 अरब डॉलर जोखिम में पड़ते हैं। इसी नुकसान से बचने के लिए एक अमेरिकी कंपनी ने महीनों पहले मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने का दावा किया है।

एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कम से कम 40 दिन पहले मौसम की जानकारी देगा earthrisktech.com के सह संस्थापक स्टीफन बेनेट ने कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह सॉफ्टवेयर बनाया है। उनका दावा है कि 40 दिन पहले ही मौसम की सटीक जानकारी दी जाएगी। कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाए गए इस सॉफ्टवेयर को एक ऑनलाइन टूल के जरिए मुहैया कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर को खासतौर पर ऊर्जा कंपनियों के लिए बनाया गया है। बेनेट कहते हैं, "पिछली सर्दियों में हमें खासी सफलता प्राप्त हुई।" अर्थ रिस्क के 80 फीसदी दावे सही निकले। कंपनी ने यूरोप और अमेरिका के पिछले 60 साल के मौमस संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया। मौसमी चक्रों का बदलाव देखा गया। बेनेट के मुताबिक समुद्री धाराओं, ताप धाराओं, दबाव और अन्य तरह के वायुमंडलीय बदलावों का भी डाटा बेस तैयार किया गया। कंपनी को उम्मीद है कि अब अमेरिका, यूरोप और एशिया की पर्यटन, ऊर्जा और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़ी कंपनियां उनके सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी दिखाएंगी। बेनेट कहते हैं,अभी मुश्किल यह हो रही हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा संख्या में ग्राहक आ रहे हैं कि मांग को पूरा करना कठिन साबित हो रहा है।

देश में ऊर्जा सुरक्षा का बदलता परिदृश्य

अरुणाभ घोष

देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। देश में ऊर्जा सुरक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। देश में ऊर्जा सुरक्षा अहम संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन संसाधनों की कीमत भी कम और अनुमान के अनुरूप होनी चाहिए ताकि आपूर्ति क्षेत्र में कोई बाधा न हो। ऐसा इसलिए ताकि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए। इसके आयामों की बात करें तो या तो पुरानी चिंताओं से संबंधित नई जटिलताएं सामने आ रही हैं या फिर ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में नई चिंताएं उभर रही हैं।

पहली बात आपूर्ति की सुरक्षा ऊर्जा के स्थानांतरण, भूराजनीति आदि से प्रभावित होती है। भारत अपनी आवश्यकता के तेल का 84 फीसदी आयात करता है। सन 2022 तक तेल आयात पर निर्भरता घटाकर 67 फीसदी करने के लक्ष्य के बावजूद इसमें इजाफा हो रहा है। साल दर साल आपूर्ति बदलने से विश्वसनीयता पर असर होता है। सन 2015 के ईरान परमाणु समझौते के पहले भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता थे सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया और वेनेजुएला। वर्ष 2016 से ईरान तीन शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया था लेकिन अब वह एक बार फिर नीचे फिसल गया है। यदि अमेरिका और इराक के बीच का तनाव बढ़ता है तो तेल आपूर्ति के एक और बड़े स्रोत के लिए जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। इस बीच 2017 में पहली बार अमेरिकी कच्चा तेल भारत पहुंचा। वह पहले ही छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हालांकि चालू वर्ष में इराक के 25 फीसदी की तुलना में उसकी हिस्सेदारी केवल 5 .7 फीसदी रही। खबरों के मुताबिक भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के अनुबंध पर काम कर रहा है। इसके बावजूद पश्चिम एशिया मध्यम अवधि में अहम बना रहेगा। नवंबर तक इस क्षेत्र ने भारत के तेल आयात में 55 फीसदी हिस्सेदारी की। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन इस क्षेत्र पर महज 43 फीसदी निर्भरता रखता है। विविधता अपनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र की घटनाएं सरदर्द साबित होती हैं। तेल कीमतें और उनका अनुमानित होना भी एक चुनौती है क्योंकि अतीत में तेल आयात बिल में काफी अनिश्चितता देखने को मिली है। इस अनिश्चितता के कारण जीवाश्म ईंधन सब्सिडी या कर राजस्व बजट का निर्धारण करना मुश्किल होता है। वित्त वर्ष 2015 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी बिल 16 .8 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2018 में 9 .4 अरब डॉलर था। ऐसे उतार-चढ़ाव औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। खासतौर पर उस समय जबकि कच्चे माल की लागत में ऊर्जा की हिस्सेदारी अधिक हो। आयातित गैस कीमतें एक और पहलू शामिल करती हैं। गैस की अधिकता के कारण एशिया में हाजिर बाजार कीमतें 4 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो गई हैं। भारत पूर्व अनुबंध के मुताबिक कतर से 85 लाख मिलियन टन गैस 9-10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर लेने को बाध्य है। ऐसे में सौदे की शर्तों पर नए सिरे से चर्चा की बात हो रही है। पेट्रोनेट अमेरिकी कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी ले सकती है, ऐसे में टेलूरियन को कम दरों पर 50 लाख टन गैस मिल सकती है। यह कीमत तय करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हद तक गैस आधारित होगी। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में समुद्री सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। भविष्य में इसमें स्थिरता और सीमा पार बिजली ग्रिड की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है, बशर्ते कि हम सीमा पार बिजली कारोबार शुरू करें। एक एशियाई सुपरग्रिड को लेकर भारी चर्चा चलती रही है। इसकी अपनी अलग तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां और निहितार्थ हैं। आपूर्ति बाधा कम करने के लिए भारत सामरिक तेल रिजर्व में निवेश करता रहा है। हालांकि सुरक्षित भंडारण की हमारी समझ व्यापक जमीनी बातों से अलग है। बैटरी तकनीक का उदय मौजूद विकल्पों को कई तरह से प्रभावित करेगा। आर्थिक तंत्र के विद्युतीकरण की गति इससे ही निर्धारित होगी। खासतौर पर लाखों सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम जिनके लिए बिजली की खराब गुणवत्ता चिंता का प्रमुख विषय है। ऊर्जा भंडारण, बिजली के मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। हाल में सौर ऊर्जा और भंडारण की सफल बोली की दर ताप बिजली के साथ प्रतिस्पर्धी रही जो उत्साहवर्धक है। वैकल्पिक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी केमिस्ट्री पर इस बात का असर होगा कि हम वितरित बिजली पर कितना भरोसा कर सकते हैं और ग्रिड आधारित व्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सामरिक तेल रिजर्व के अलावा भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था और उन अहम खनिजों के सामरिक रिजर्व के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा जो विभिन्न ऊर्जा भंडारण कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऊर्जा में बदलाव चौथी तरह के जोखिम सामने लाता है जिन्हें वित्तीय रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से लडने के प्रयास कंपनियों की बैलेंस शीट पर जीवाश्म ईंधन भंडार के मूल्य को लेकर संदेह उत्पन्न करते हैं। फाइनैंशियल टाइम्स के मुताबिक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने की स्थिति में सरकारी तेल कंपनियों का करीब आधा भंडार बेकार हो जाएगा। कई तेल निर्यातक कंपनियों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। उस स्थिति में 13 बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को 360 अरब डॉलर मूल्य का नुकसान होगा।

दुनिया के बड़े निवेशक इस बदलती हकीकत को आकार दे रहे हैं। दिसंबर में 631 गैर अमेरिकी निवेशक जिनके पास 37 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, ने सरकार से कहा कि वह जलवायु संबंधी कदमों को गति दे। गत माह 7 लाख करोड़ डॉलर की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा कि वह उच्च स्थायी जोखिम वाले निवेश से बाहर निकलेगी। कोयले के साथ ज्यादा जोखिम है। मौजूदा कोयला भंडार का बमुश्किल चौथाई हिस्सा दो डिग्री सेल्सियस वाली परिस्थिति में जलाया जा सकता है। सन 2011 से अब तक कोयला खनन कंपनियों के मूल्य में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोयला उत्पादन बढ़ाने की घोषणाओं के बीच भारत को फंसी परिसंपत्ति के जोखिम का आकलन करना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा तकनीक, आर्थिकी या भूराजनीति से प्रभावित हुई है। अब इन सभी मोर्चों पर बदलाव हो रहे हैं। ऊर्जा की मांग भी पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है। पुरानी चिंताएं और नई समस्याएं घुलमिल गई हैं। भारत को आगे रहने की तैयारी रखनी होगी।

(लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)

वायु प्रदूषणः भारत को करनी होगी ठोस पहल

अरूमिता रॉय चौधरी

भारत में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए परस्पर सहमत कार्य योजना के आधार पर क्षेत्रीय सहयोग और दायित्वों से संबंधित ढांचे के निर्माण का समय आ गया है जिसमें पर्याप्त संसाधनों की सहायता से लक्ष्यों का निर्धारण भी शामिल है। भारत के एनसीएपी ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण और अंतरराज्यीय समन्वय के विचार को मान्यता दी है। इसमें उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय स्रोत आबंटन अध्ययनों से प्राप्त जानकारी को शामिल करके एक व्यापक क्षेत्रीय योजना बनाने की जरूरत है। इसमें कई उपायों को सूचीबद्ध किया गया है जो अनेक क्षेत्राधिकारों में पड़ते हैं और जिनकी प्रकृति क्षेत्रीय है। इनमें ईंधन संबंधी सख्त मानदंड, सड़क की बजाय रेल और जलमार्गों का इस्तेमाल, गाड़ियों का आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीतियां और संगत और स्पष्ट कराधान नीतियां शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र में यह कड़े औद्योगिक मानदंडों और स्वच्छ ईंधन तथा प्रौद्योगिकियों की सिफारिश करता है। निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली को प्राथमिकता की गई है।

इसके अलावा, एनसीएपी ने खाना बनाने के लिए घरेलू ईंधन के तौर पर लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने तथा घरेलू स्तर पर ऐसे ही अन्य उपाय करने का आह्वान किया है। पराली जलाने जैसे विशेष मामलों के संबंध में कार्यक्रम बनाने को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इन उपायों को क्षेत्रीय प्रतिमानों में शामिल जाना चाहिए और इन्हें अलग से या स्थानीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। अब तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई व्यापक कार्य योजना एकीकृत क्षेत्रीय योजना का एकमात्र उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस योजना को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के तहत अधिसूचित किया था। यह एकमात्र एकीकृत योजना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र की सभी रणनीतियों में समान कार्यान्वयन अपेक्षित है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में विषमता है। दिल्ली में, सभी क्षेत्रों में कोयले सहित दूषित ईंधन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है, ट्रकों की संख्या और कारों के डीजलाइजेशन में कमी आई है, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है, डीजल जनरेटर सेटों पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली की आपूर्ति में सुधार किया गया है, घरों में ठोस ईंधन का उपयोग काफी कम हो गया है और पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं जैसे उपायों को अपनाया गया है।

एनसीआर के अन्य राज्यों ने सभी क्षेत्रों में प्रदूषण के लड़ने में समान तेजी नहीं दिखाई है। इसलिए, यह सच है कि दिल्ली को अब भी छोटी और मझोली इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की विषमता को दूर करने, वाहनों की अधिक संख्या से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और औद्योगिक तथा नगरपालिका के कचरे को जलाने की गति को धीमा करने की रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही अन्य राज्यों को अपने स्तर पर आगे बढ़ने और मानदंडों को पूरा करने के संबंध में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। आगामी दशक में दिल्ली-एनसीआर को कोयले और अन्य दूषित ईंधनों से स्वयं को पूरी तरह मुक्त करना होगा तथा सभी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन जैसे बिजली और प्राकृतिक गैस तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जैसे ट्रकों और डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को हटाना होगा और डीजल के इस्तेमाल को समग्र रूप से नियंत्रित करना होगा। साथ ही, कचरे को जलने से रोकने के लिए नगरपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार करके अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाना होगा। तकनीकी रूप से, इस स्तर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।वायु (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19, राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में, इस प्रावधान का बहुत ही सीमित अर्थ लिया गया है और ऐसे नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा केवल गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित है।

एकीकृत योजना और अनुपालन हेतु अधिक न्यायालयों को शामिल करने के लिए इस प्रावधान के दायरे और उद्देश्य को व्यापक रूप दिया जा सकता है। वायु अधिनियम, 1981 के दायरे में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों या गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों को परिभाषित करते हुए भौगोलिक प्रसार और प्रदूषण स्रोतों की कवरेज को शामिल करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को बदलना होगा। इससे शासन का ढांचा और अंतरराज्यीय समन्वय मजबूत होगा जो वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बदलाव की शुरुआत की जाए ताकि सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों की व्यापक और अधिक प्रभावी भागीदारी हो सके।

उत्तरप्रदेश में ओलों से फसलें हुई बर्बाद

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के किसान रिंकू कटियार ने 96 बीघा आलू की खेती की थी। अब तक 54 बीघा आलू की खुदाई हो गई थी, लेकिन अभी भी 30 बीघा आलू खेत में पड़ा है। 5-6 मार्च को भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से यह आलू खराब हो जाएगा। सुल्तानपुर जनपद के कूरेभार ब्लॉक के लोकेपुर गांव के किसान अंजनी वर्मा के खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और मटर की फसल को नुकसान हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश टिकैत का अनुमान है कि दो दिन की बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 40 फीसदी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं, बारिश और ओले की वजह से हरियाणा के 18 जिलों में सरसों और गेहूं के फसल को नुकसान हुआ है। गिरदावरी के आदेश के बाद जुटाई प्रथमिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 517 गांवों में 50318 हेक्टेयर (करीब 1.24 लाख एकड़) में लगी फसल 50 से 75 फीसदी तक प्रभावित हुई है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च से 5 मार्च के बीच देश के कुल 683 मौसम क्षेत्रों में से 222 में से भारी बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सामान्य से 60 फीसदी अधिक बारिश होने को भारी बारिश की श्रेणी में रखा जाता है। इसके विपरीत 265 जिलों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिससे पता चलता है कि देश के बड़े हिस्से में या तो बहुत ज्यादा बारिश हुई या फिर बारिश नहीं हुई। यह पैटर्न पिछले कुछ वर्षों से लगातार बना हुआ है। जहां बारिश हो रही है तो सामान्य से बहुत अधिक बारिश हो रही है और कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। मानसून के मौसम में जब देश में अधिकांश बारिश होती है तो इस पैटर्न की वजह से एक ही क्षेत्र में एक साथ बाढ़ और सूखा पड़ता है जिससे लोगों लिए समस्या पैदा होती है।

कोयले के साथ ज्यादा जोखिम

गत माह 7 लाख करोड़ डॉलर की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा कि वह उच्च स्थायी जोखिम वाले निवेश से बाहर निकलेगी। कोयले के साथ ज्यादा जोखिम है। मौजूदा कोयला भंडार का बमुश्किल चौथाई हिस्सा दो डिग्री सेल्सियस वाली परिस्थिति में जलाया जा सकता है। सन 2011 से अब तक कोयला खनन कंपनियों के मूल्य में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोयला उत्पादन बढ़ाने की घोषणाओं के बीच भारत को फंसी परिसंपत्ति के जोखिम का आकलन करना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा तकनीक, आर्थिकी या भूराजनीति से प्रभावित हुई है। अब इन सभी मोर्चों पर बदलाव हो रहे हैं। पुरानी चिंताएं और नई समस्याएं घुलमिल गई हैं। भारत को आगे रहने की तैयारी रखनी होगी।

मौसम और अपराध के बीच है गहरा रिश्ता

एजेंसियां :मौसम और आपराधिक घटनाओं के बीच क्या कोई संबंध है? क्या इस तरह की जानकारी अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के काम आ सकती है? जर्मनी में एक अपराध विज्ञानी ने इस संबंध में एक दिलचस्प प्रयोग किया है। 1748 में फ्रांस के बारों मोंटेस्क्यू ने कहा था कि कानूनों को मौसम के हिसाब से बनाया जाना चाहिए क्योंकि गर्मी या सर्दी का असर अपराधियों पर पड़ सकता है। क्रिमिनॉलजिस्ट यानी अपराध और उसके पीछे की मानसिकता को जांच रहे मनोवैज्ञानिक आंद्रेआस लोमायर कहते हैं कि मौसम और जुर्म के बीच का रिश्ता पहले भी लोगों ने समझने की कोशिश की है। हैम्बर्ग की पुलिस के साथ काम कर रहे लोमायर अब हर दिन मौसम की जानकारी मंगवाते हैं।वैसे तो पुलिस के एक थाने को हमेशा दूसरे थाने के मौसम की जानकारी रखनी पड़ती है ताकि आपात स्थिति में पता लगाया जा सके कि किसी दूसरी जगह के पुलिस अधिकारी आने की हालत में हैं भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद अपराध और मौसम के बीच का रिश्ता साफ नहीं हो पाया है। लोमायर ने पुलिस के आपराधिक आंकड़ों को मौसम की सूचना के साथ मिलाकर देखा। वह कहते हैं कि जब आप मौसम के बारे में जानकारी को दिन में हर एक घंटे के लिए बांटते हैं वह भी पिछले 20 सालों के लिए तो आपको तीन करोड़ 60 हजार जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा एक लाख 75,000 छोटी जानकारियां जो पुलिस आंकड़ों से मिलती है।

कैसे पता चला

अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोमायर ने 20 लाख जानकारियां अलग

की और हर एक अपराध के बारे में तथ्यों की जांच की। उससे पता चला कि ऐसा कोई मौसम नहीं है जो हमेशा अपराध को बढ़ावा देता हो। लेकिन अपराध भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो मौसम से प्रभावित नहीं होते जैसे चोरी, दुकान पर डाका डालना, जहर देना, धोखाधड़ी और गाड़ी चोरी करना। लेकिन कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जो मौसम की वजह से बढ़ जाते हैं। जैसे बलात्कार। इस सिलसिले में लोमायर कहते हैं कि गर्मी जितनी बढ़ती है, इस तरह के जुर्म ज्यादा होते हैं। और आंकड़ों से भी यही साबित होता है। एक डिग्री सेल्सियस के बढ़ने के साथ साथ जुर्म रोजाना 0 ।7 गुना बढ़ते हैं ।अगर हफ्ते में धूप वाले दिन को अलग देखा जाए तो आंकड़े और साफ होंगे। लोमायर का कहना है कि अगस्त में अगर किसी शनिवार को ज्यादा गर्मी होती है तो उस दिन 82 बर्बर अपराधों के होने की संभावना है। मार्च में एक ठंडे दिन में यह आकंड़ा सिर्फ 51 के आस पास रहता है ।और मजेदार बात यह है कि एक धूप वाले दिन में साइकिलों की चोरी भी ज्यादा होती है। आंकड़े देते हुए वे कहते हैं कि मार्च के एक बारिश वाले रविवार में 19 साइकलें चोरी हुई थीं लेकिन जून के एक मंगलवार में 63 ऐसे किस्से हुए।

सूरज डूबा और चोर निकले

साथ ही दिन के छोटे होने के साथ रात का अंधेरा भी जुर्म को बढ़ावा देता है ।लोमायर के आंकड़े कहते हैं कि एक घंटा ज्यादा अंधेरा होने से एक अपराध ज्यादा होगा। लेकिन मौसम ठंडा होते ही यह आंकड़ा कम भी हो जाएगा। जब दिन बिलकुल छोटे और ठंडे हो जाएंगे तो इस रिश्ते के बारे में बोलना कठिन हो जाएगा। जब बर्फ पड़ती है तो हर दिन छह अपराध कम होते हैं। मतलब साफ है, चोरों को गर्मी और अंधेरा पसंद है। इस साल फरवरी में हैम्बर्ग के लोग शीत लहर से कांप रहे थे। जाहिर है ऐसे में चोर भी अपने घरों से निकलते कतरा रहे थे और पूरे शहर में पुलिस ने केवल दो अपराध दर्ज किए, जिनमें लोगों ने गाड़ी की रियर व्यू मिरर चुराने की कोशिश की ।अमेरिकी राज्य टेनेसी के शहर मेम्फिस में भी पुलिस कंप्यूटर के जरिए मौसम और अपराध के रिश्ते को खोज रही है। एक खास सॉफ्टवेयर, क्रश के जरिए चोरी के दिन को लेकर अपराधिक आंकड़ें, समारोह, आर्थिक आंकड़ों और मौसम के प्रभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है। 2005 से वहां की पुलिस यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद मेम्फिस में अपराध 30 फीसदी कम हो गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस रांची के ''कोयला कक्ष'' में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर, 2019) बैठक आज संपन्न हुई। सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह के नेतृत्व में कंपनी राजभाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में मुख्यालय सहित कंपनी के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधिगण ने भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक (गुणवता) आई.सी. मेहता ने उपस्थित सभी से कहा कि आप सभी अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करे जिससे राजभाषा का विकास शत प्रतिशत हो। उनहोंने राजभाषा में और बेहतर कार्यनिष्पादन करने के लिए सभी कर्मियों को प्रेरित किया। राजभाषा विभाग द्वारा एक ई-टुलकित हर विभाग को दिया जायेगा जिससे हिन्दी में कार्यनिष्पादन और सुगम हो सके।

नवनिर्मित पे एंड यूज शौचालय का उद्घाटन

रांची :04.03.2020 को राँची रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नवनिर्मित पे एंड यूज शौचालय का उद्घाटन माननीय महापौर रांची, श्रीमती आशा लकड़ा ने किया इस अवसर पर माननीय उप महापौर रांची, श्री संजीव विजयवर्गीय, मंडल रेल प्रबंधक, श्री नीरज अम्बष्ठ एवं वार्ड 14 के पार्षद श्री दिनेश राम उपस्थित थे । शौचालय में पुरुषों के लिए चार, महिलाओं के लिए तीन , बच्चों के लिए एक तथा दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ एक शौचालय की व्यवस्था की गई है। शौचालय में स्नान करने के लिए पाँच रूपये एवं शौच के लिए पाँच रूपये का शुल्क लिया जाएगा तथा बच्चों एवं दिव्यांगों के लिए शौचालय सुविधा निशुल्क होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रांची, संजीव कुमार, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी सुहास लोहकरे, मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवराज बनर्जी, सुलभ इंटरनेशनल के मानद नियंत्रक आनंद शेखर एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सीसीएल अंतर क्षेत्रिय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन

संवाददाता रांची : सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा तीन दिवसीय 05 से 07 मार्च तक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम, खेलगांव रांची में सीसीएल इंटर क्षेत्रिय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सीसीएल के मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों के 135 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहें हैं। प्रतियोगिता का आयोजन में प्रबंधक (खेल) आदिल हुसैन एवं उनकी टीम सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं टेबल टेनिस (ओपेन सिंगल) में का नाम इस प्रकार है विजयी प्रतिभागी एस एन भटटा एवं उप विजेता असलम साहेयर, ओपेन डबल में विजेता एस हुसैन एवं अभिषेक कलसी और उप विजेता एस. सिन्हा एवं असलम सायर जबकि वेटरन सिंगल में विजय प्रतिभागी पीके चक्रवर्ती और उपविजेता वी. तिर्की वेटरन डबल में विजेता पी.के. चक्रवर्ती एवं वी तिर्की और उपविजेता सुनिल सहाय एवं संजय शर्मा। आज के दूसरे दिन के बैडमिंटन मैच के सेमिफाईनल में सीआरएस बरकाकाना मंजू देवी एवं सोनम कुमारी विजेता रही। पुरुष टीम चैम्पीयनशीप में मुख्यालय, रांची एवं बरका सयाल की टीम पहुच चुकी है।

दानापुर मंडल के किऊल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित होंगी

निम्नलिखित ट्रेनें रद्द रहेंगी

1. ट्रेन संख्या 07009 सिकंदराबाद - बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 22.03.2020 एवं 29.03.2020 को सिकंदराबाद से रद्द रहेगी । **2.** ट्रेन संख्या 07010 बरौनी - सिकंदराबाद एक्सप्रेस दिनांक 25.03.2020 एवं 01.04.2020 को बरौनी से रद्द रहेगी । **3.** ट्रेन संख्या 17005 हैदराबाद - रक्सौल एक्सप्रेस दिनांक 19.03.2020 एवं 26.03.2020 को हैदराबाद से रद्द रहेगी । **4.** ट्रेन संख्या 17006 रक्सौल - हैदराबाद एक्सप्रेस दिनांक 22.03.2020 एवं 29.03.2020 को रक्सौल से रद्द रहेगी। **5.** ट्रेन संख्या 17007 सिकंदराबाद - दरभंगा एक्सप्रेस दिनांक 17.03.2020, 21.03.2020, 24.03.2020, 28.03.2020 एवं 31.03.2020 को सिकंदराबाद से रद्द रहेगी **6.** ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा - सिकंदराबाद एक्सप्रेस दिनांक 20.03.2020, 24.03.2020, 27.03.2020, 31.03.2020 एवं 03.04.2020 को दरभंगा से रद्द रहेगी ।

निम्नलिखित ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी

1) ट्रेन संख्या 18621 पटना - हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 19.03.2020 से 02.04.2020 तक परिवर्तित मार्ग गया - गोमो - राजाबेरा होकर चलेगी । 2) ट्रेन संख्या 18622 हटिया - पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 18.03.2020 से 01.04.2020 तक परिवर्तित मार्ग राजाबेरा - गोमो - गया होकर चलेगी ।

सी.सी.एल. के सीवीओ ए.के. श्रीवास्तव का भावभीनी विदाई

संवाददाता रांची : सी.सी.एल. के सीवीओ श्री ए.के. श्रीवास्तव को सात मार्च संध्या सी.सी.एल. परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय के ''विचार मंच'' में ''सम्मान समारोह'' का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। मुख्यालय, रांची में आयोजित सम्मान समारोह में सी.सी.एल. के सीएमडी गोपाल सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल ने समारोह के केंद्र बिन्दु ए.के. श्रीवास्वतव का अभिनंदन एवं स्वागत किया तथा पुष्पमाला, स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष, श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण एवं अन्य ने पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया।

सीएमपीडीआई विप्स ने करूणा अनाथ आश्रम के बच्चों से भेंट की

रांची : फोरम ऑफ वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर करूणा अनाथ आश्रम, बरियातु जाकर वहां के बच्चों से मुलाकात की तथा इस अवसर पर मानवता के लिए सार्थक बनाने की एक छोटी सी पहल की गयी।

इस मौके पर फोरम ऑफ वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई द्वारा वहां के बच्चों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैस लेक्टोजन, डाईपर, कपड़े, जॉनसन बेबीसोप, जॉनसन बेबी ऑयल, जॉनसन बेबीपाउडर, हवाई चप्पल, बिस्किट तथा नमकीन आदि समान भेंट की गयी। यह संस्था बच्चों के पालन-पोषण, चिकित्सा तथा उनकी शिक्षा के लिए भी कार्य करता है। फोरम ऑफ वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई की ओर से महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्रीमती सुनीता मेहता, चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 (श्रीमती) शिल्पी स्वरूप, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) श्रीमति ममता टोप्पो, कार्यालय अधीक्षक श्रीमति मीराकुमारी जबकि करूणा आश्रम की ओर से संचालिका श्रीमति संगीता उपस्थित थीं।

होली के मद्देनजर मिठाईयों एवं खाद्य सामग्रियों की होगी जांच

संवाददाता

●उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे के निदेशानुसार जांच टीम गठित●अनुमण्डल पदाधिकारी, रांची ने कहा, होलसेल विक्रेताओं के गोदामों की भी की जाएगी जांच● आमजनों के जानमाल से खिलवाड़ को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, दोषियों के खिलाफ़ होगी सख्त कार्रवाई": लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी रांची

रांची :होली के त्योहार को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटी मिठाईयां बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उक्त हेतु दिनांक- 04/03/2020 से 09/03/2020 तक रांची जिलांतर्गत विभिन्न मिष्ठान भंडारों एवं खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही मौके पर मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच हेतु जमा किये जाएंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी सदर रांची लोकेश मिश्रा ने कहा कि "पर्व-त्योहार के मौकों पर मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। जिसकी वजह से आपूर्ति की कमी होने की वजह से कई दफ़ा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं या मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने की शिकायतें मिलती हैं। इस तरह के मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। जिससे कि धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जा सके एवं आमजनों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।लोकेश मिश्रा ने कहा कि, "इस दौरान रांची के कांके रोड, हरमू रोड, मेन रोड, बरियातू रोड, धुर्वा, डोरंडा, बिरसा चौक, स्टेशन रोड आदि स्थानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरे राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 41 महिलाओं को सम्मानित किया गया

संवाददाता रांची :08.03.2020 को छात्र क्लब एवं आस्था जीवन के संयुक्त तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन श्री विश्वनाथ शिव मंदिर प्रांगण, पिस्का मोड़, रातू रोड, राँची में शिव किशोर शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यअतिथि हिन्दु जागरण मंच के प्रदेश संरक्षक प्रिंस आजमानी, विशिष्ट अतिथि विश्वनाथ शिव मंदिर के संस्थापक शैलेश्वर दयाल सिंह, छाया फिल्म के प्रोडॅसर लक्ष्मन मुण्डा, मौरनिंग ग्लोरी स्कुल बाजरा के निदेशक सिमा मुण्डा, प्रसिद्ध समाजसेविका शिवानी प्रकाश, डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, विश्वकर्मा युवा सुरक्षा मंच के मुख्य संयोजक संतोष कुमार श्रेयांस, संरक्षक धीरेन्द्र प्रसाद, छात्र क्लब ग्रुप के संरक्षक लाल संजय नाथ शाहदेव, सुनील कुमार तिवारी, संजीव चैधरी, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष महुआ माँझी, भाजपा नेत्री सुमन मिश्रा, सुचिता सिंह, परशुराम महतो, आस्था जीवन के सचिव विनोद कुमार साहू मौजूद थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खेल-कूद, कला-सांस्कृति, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि, ब्यूटीशियन, मॉडलिंग, आदि में उत्कृष्ट एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले 41 महिलाओं को प्रमाण-पत्र, अंग-वस्त्र, मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। संस्था की ओर से निम्नलिखित महिलाओं को सम्मानित किया गया- रागनी देवी, नीलम शर्मा, प्रिया कुमार गुप्ता, रविन्दर कौर, चन्द्रकांता गुप्ता, संध्या देवी, नीतू गुप्ता, प्रभा तिवारी, काव्या शर्मा, मुस्कान कुमारी, शकुन्तला देवी, निशा मल्होत्रा, शैलबाला, नीतिशा कुमारी, अनीता कुमारी, नीलम किरण, अंजना प्रियदर्शनी, पिया कुमारी, पायल सोनी, प्रिया कुमारी, सुनिता चैधरी, मंजू तिवारी, सौम्या तिवारी, नम्रता सोनी, प्रज्ञाश्री, बबली देवी, ईशा कुमारी, शीला साहू, शीला देवी, कुमूद झा, सुजाता भगत, किरण देवी, शोभा कुमारी, मोना देवी, खुशबू पटेल, शोभा वर्णवाल, ममता रानी, प्रीति गुप्ता, रीना सिंह, सिमरन देवी, पूनम झा,। कार्यक्रम की समाप्ति होली मिलन के साथ हुई।

इस शुभ कार्य के लिए राँची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ ने आयोजन कमिटि को बधाई दिए।

होली आपसी सौहार्द एवं भाईचारा का पर्व - शिवनंदन पाठक

रांची :7 फरवरी को डी.ए.भी. शिक्षादीप, कमड़े, रातू रोड में होली मिलन समारोह का आयोजन निदेशक शिवनंदन पाठक के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। शिवनंदन पाठक ने कहा होली आपसी सौहार्द, भाईचारे एवं सादगी का त्यौहार है। इस पर्व में कादो, कीचड़, गंदगी, खराब रंगों का बिल्कुल इस्तमाल न करें। एक ओर जहाँ गंदगी से तरह-तरह की बिमारियाँ होती हैं वहीं पानी की बर्बादी भी होती है। डॉ. अनुज कुमार पटेल ने रासायनिक रंग-अबीर से होने वाले बिमारियों को विस्तृत रूप से बताया।

अखिल घाटी डीवीसी शतरंज प्रतियोगिता सम्पन्न

सिदाम

रांची :हजारीबागः दामोदर घाटी निगम हजारीबाग में अखिल घाटी डीवीसी शतरंज प्रतियोगिता 2019-20 का आयोजन किया गया।इस प्रतियोगिता में दामोदर घाटी निगम की 9 परियोजनाओं के खिलाड़ियों ने भाग लिया।तीन दिन(02 मार्च से 04 मार्च) तक चले इस आयोजन में 35 खिलाडियों ने टीम वर्ग में और व्यक्तिगत वर्ग में भाग लिया। इसमें हजारीबाग की टीम स्पर्धा में विजेता घोषित हुई। हजारीबाग शतरंज टीम में रूपेश कुमार महतो, नवीन कुमार, टीम के कप्तान स्वप्न कुमार भद्रो और धीरज कुमार थे।बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की टीम उपविजेता घोषित हुई। हजारीबाग टीम को कुल 12 प्वॉइंट 5 अंक प्राप्त हुए और बोकारो थर्मल पावर टीम को कुल 10 अंक प्राप्त हुए।व्यक्तिगत स्पर्धा में रूपेश कुमार महतो सभी 6 मैच जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किए जो कि हजारीबाग परियोजना से हैं।उन्हें प्लयेर ऑफ़ द टूर्नामेन्ट चुना गया।टॉप सिक्स में आए दीपक कुमार साहू बोकारो थर्मल, अजय कुमार बनर्जी रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, रजत कांति खटवा अंडाल, नवीन कुमार हजारीबाग, बादल मण्डल को पुरस्कृत किया गया।

मौके पर आर्य शर्मा उप मुख्य अभियन्ता टीएससी जीएमडी, शम्भु वर्णवाल, डॉ संज्ञा दास, अरुण कुमार सिंह, कंचन कुमार सिंह, धर्मेन्द्र प्रसाद आदि सम्मिलित हुए।कार्यक्रम के आयोजन औकारनाथ, संजय कुजर,चेतानारायण,शंकर सिंह,मोहन, बालेश्वर हजाम ने सराहनीय योगदान दिया। इस प्रतियोगिता में विजेता बनी दामोदर घाटी निगम हजारीबाग की टीम को संजय कुमार निदेशक भूमि संरक्षण विभाग परियोजना प्रमुख के सिन्हा, जितेंद्र झा, संजय कुमार सिंह ने बधाई दी।

कोल इंडिया अध्यक्ष ने सी.सी.एल. के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की।

संवाददाता रांची : सी.सी.एल. मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल ने सी.सी.एल. के कार्य निष्पादन की समीक्षा की। बैठक में सी.सी.एल. के सीएमडी श्री गोपाल सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह, निदेशक (वित्त) श्री एन.के. अग्रवाल, सीवीओ, श्री ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी), बीसीसीएल श्री चंचल गोस्वामी सहित सीसीएल मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक से जुड़े रहे।

बैठक में विशेषकर कोयला उत्पादन, प्रेषण, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने अध्यक्ष, कोल इंडिया श्री प्रमोद अग्रवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से कंपनी के कार्यनिष्पादन, योजनाओं, उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में अध्यक्ष, कोल इंडिया को विस्तार से जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में प्रमोद अग्रवाल ने कंपनी के भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण सबंधी स्वीकृति की सीधी जानकारी ली। श्री अग्रवाल ने सभी बिन्दुओं को ध्यान से सुना और इस दिशा में कोल इंडिया की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आशवासन दिया। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया सहित कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) सभी अनुषंगी कंपनियों को हरसंभव सहयोग प्रदान करती आयी है और आगे भी हमारा सहयोग सदैव मिलता रहेगा। हम सभी को मिलकर देश की उर्जा शक्ति को सुदृढ़ करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1000 मिलियन टन यानी 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस चुनौती को हम सभी सम्मिलित प्रयास से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीसीएल के सीएमडी श्री सिंह ने कहा कि सीसीएल वित्तीय वर्ष 2012-13 में जहाँ 48 मिलियन टन कोयला उत्पादन से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और आज उसी संसाधन एवं श्रम शक्ति के साथ लगभग 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने जा रहा है। इस विकास की गति में केन्द्र सरकार, कोयला मंत्रालय एवं राज्य सरकार का सहयोग सदैव मिलता रहा है। साथ ही इस उपलब्धि में श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण, जेसीएससी, वेलफेयर बोर्ड एवं सेफ्टी बोर्ड सहित सीसीएल वृहद परिवार के प्रत्येक सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सी.सी.एल. 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को आने वाले समय में प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

ऑल वेदर रोड से गंगा और पहाड़ को हो रहा नुकसान

एजेंसियां :बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी चार धाम मार्ग परियोजना जिसे ऑल वेदर रोड कहा जा रहा है की जरूरत पर ही सवाल उठ रहे हैं।सड़क चौड़ी करने के लिए जहां पिलर और पुश्ते बनाकर काम हो सकता था, वहां भी अंदर की तरफ पहाड़ को काटा गया। जहां जरूरत नहीं थी, वहां भी पहाड़ काटे गए। ऑल वेदर रोड के नाम पर पूरे हिमालयी क्षेत्र में जो तोड़फोड़ हुई है, ये पहाड़ पर अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। विजय जड़धारी की आवाज़ ये कहते हुए कुछ कांपती सी है। जड़धारी कहते हैं कि अंदर की तरफ बहुत ज्यादा पहाड़ काटने से ठेकेदारों का तो मुनाफा हो गया। सड़क निर्माण के लिए जरूरी रेत, पत्थर, बजरी, रोड़े सब वहीं निकल गए। उन्हें बाहर से सिर्फ सीमेंट या कोलतार लाना होता है। वह कहते हैं कि जहां सड़क को चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी या जो क्षेत्र भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, वहां भी पहाड़ काटे गए। यही नहीं, बेतरतीब पहाड़ काटने से पानी के सैकड़ों स्रोत खत्म हो गए। पहाड़ काटने के लिए किसी भूगर्भ विज्ञानी की राय तो ली जानी चाहिए थी। गंगा नदी के किनारे ही स्टोन क्रेशर लगाए गए हैं। जहां आसपास आबादी है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। वहीं नदी किनारे स्टोन क्रशर होने से

जलीय जीवों पर भी खतरा आ गया है। जड़धारी बताते हैं कि यहां बेहद दुर्लभ किस्म की मछलियां पायी जाती हैं। नदी में जा रहा मलबा इन मछलियों के लिए घातक साबित हो रहा है।

ऑल वेदर रोड के लिए पहाड़ तो धराशायी किये ही जा रहे हैं, उनकी आड़ में बेवजह पेड़ों को भी काटा जा रहा है। किसान विजय जड़धारी की ये भी शिकायत है कि टिहरी में उनके गांव नागनी में पहाड़ काटने के नाम पर 50-60 वर्ष पुराने पेड़ तक काट दिए गए। जो सड़क के रास्ते में नहीं आ रहे थे। इसके लिए उन्होंने डीएफओ और जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। वह कहते हैं कि पहाड़ के इस तोड़फोड़ से तैयार हुए नए भूस्खलन ज़ोन अगले 10-15 वर्षों तक यहां के लोगों को रुलाएंगे। वह बताते हैं कि घर बनाने या मनरेगा के तहत निर्माण के लिए जब पत्थर या बजरी खोदी जाती है तो राजस्व विभाग उनसे रॉयल्टी वसूलता है, लेकिन ऑल वेदर रोड के निर्माण में लाखों-लाख टन पत्थर, रोड़ी और डस्ट बनाने के लिए क्रशर प्लांट लगे हैं, जो हिमालय की शुद्ध हवा को प्रदूषित कर रहे हैं लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आंख मूंदे हुए है।विजय जड़धारी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा और बताया कि एक तरफ गंगा को बचाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि लगाई जा रही है, वहीं ऑल वेदर रोड बनाने में लगे लोग गंगा ही नहीं अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, कोसी समेत सैंकड़ों गाड-गधेरों में मलबा डाल रहे हैं। उत्तरकाशी में रहने वाले दिगबीर बिष्ट कहते हैं कि ऑल वेदर रोड के नाम पर जगह-जगह जरूरत से ज्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। वह संशय जताते हैं कि इसमें माफिया की पूरी साठगांठ है। उनके मुताबिक जिले के डूंडा ब्लॉक में गंगा किनारे करीब 8-9 स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। उन्हें तो कच्चा माल चाहिए। कहीं कच्चे पहाड़ हैं, कहीं पक्के पहाड़ हैं। जहां अच्छा मैटर दिखता है, वहां पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं। इसके लिए ब्लास्टिंग भी की जा रही है। फिर ट्रकों में मलबा भरकर गंगा किनारे स्टोन क्रशर में ले जाया जाता है। दिगबीर अफसोस जताते हैं कि गंगा को ही डंपिंग जोन बना दिया गया है।

ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन के लिए बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा को भी जरूरत से ज्यादा पहाड़ काटने की शिकायतें मिलीं। वह कहते हैं कि ऑल वेदर रोड के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने इस तरह की शिकायत की, लेकिन उनकी टीम स्थानीय लोगों की इस शिकायत की पुष्टि नहीं कर पायी। उनके मुताबिक पहाड़ के घुमावों पर सड़क दूसरे हिस्सों से जरूर कुछ चौड़ी नज़र आई। जो कि वाजिब है। इसकी जरूरत होती है ताकि मोड़ पर लोग दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां देख सकें। इसके अलावा जगह-जगह पर लोगों ने पहाड़ ज्यादा काटने को लेकर शिकायत की। लेकिन इन सवालों पर कमेटी को अभी पड़ताल करनी है। हमने एक दिन में करीब 100-150 किलोमीटर तक सफ़र किया। ताकि हम समस्याओं को खुद महसूस कर सकें।

चोपड़ा कहते हैं कि सड़क की चौड़ाई को लेकर भी हमें हिल रोड मैन्यूज़ को समझना होगा। फिलहाल ऑल वेदर रोड के तहत सड़क की स्टैंडर्ड चौड़ाई 12 मीटर है। जिसमें से दोनों छोर पर मिलाकर करीब 3 मीटर तक जगह छोड़नी होगी। वह बताते हैं कि ईपीसी के आधार पर रोड बनाने का जिम्मा कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। सड़क के डिजायन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकता है। बड़े बदलाव के लिए उसे सड़क का रि-ड्राफ्ट सबमिट करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले इस मामले पर भी संबंधित अफसरों से पूछताछ करेगी।

सीएसआर कॉन्क्लेव' में सीसीएल का भव्य स्टॉल

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम द्वारा 03 मार्च, 2020 को होटल अशोका, नई दिल्ली में 'सीएसआर कॉन्क्लेव' का सफल आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का विषय था ''सीपीएसई द्वारा आकांक्षात्मक जिलों- सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर के विभिन्न पहल से परिवर्तन लाना।

इस कॉन्कलेव में अन्य उद्योग संस्थाओं सहित सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) ने भव्य स्टॉल लगाकर अपने सीएसआर के दिशा-निर्देश को दर्शाया। स्टॉल का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा किया गया। स्टॉल में सीसीसल द्वारा सीएमडी श्री गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में किये जा रहे सीएसआर के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कौशल विकास आदि कार्यों को छायाचित्र के माध्यम से दिखाया गया।

फोटो न्यूज

रांची रेल मंडल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर दिनांक 1 मार्च से 10 मार्च तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है दिनांक 8 मार्च 2020 (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को रांची रेल मंडल द्वारा एक ट्रेन का परिचालन किया गया जिस का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया ।

होली क्यों मनाई जाती है, क्या है इसकी कथा?

होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिन्दू लोग रहते हैं वहाँ भी धूम-धाम के साथ मनाया जाता है पहले दिन को होलिका जलायी जाती है, दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर-गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजा कर होली के गीत गाये जाते हैं और घर-घर जा कर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने-बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इस-के बाद स्नान कर के विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन कर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग-रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश-वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही पर इनको उत्कर्ष तक पहुँचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग-बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं।

होली का त्यौहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग-बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूँ की बालियाँ इठलाने लगती हैं। बच्चे-बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियाँ भूलकर ढोलक-झाँझ-मंजीरों की धुन के साथ नृत्य-संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ़ रंगों की फुहार फूट पड़ती है।

होली की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा

यह त्योहार किसानों के रबी की फसल के तैयार होने के कारण भी मनाया जाता है। होली को मनाने का मुख्य उद्देश्य केवल एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाना और प्रेम और भाईचारे के साथ रहना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस प्रवृत्ति वाला हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रह्लाद की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर बहुत परेशान था। उसने प्रह्लाद का ध्यान ईश्वर से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली।अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को जान से मारने का फैसला किया। उसने इसके लिए अपनी बहन होलिका से आग्रह किया। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान में एक शाल दी थी जिसे पहनने से वो कभी भी आग में नहीं जलेगी।इस वरदान को पाने वाली होलिका ने सोचा कि वह प्रह्लाद को आग में जाएगी और खुद शाल ओढ़ लेगी। इस तरह प्रह्लाद की जलने से मृत्यु हो जाएगी जबकि शाल उसको सुरक्षित रखेगा। हालांकि हुआ इसके ठीक विपरीत ऐन मौके पर भगवान विष्णु ने हवा का ऐसा झोंका चलाया कि शाल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गयी। भगवान ने प्रह्लाद की रक्षा की और होलिका का दहन हो गया। इस तरह सभी ने अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक स्वरूप मिठाइयां बांटी और होली के त्योहार की शुरुआत हुई। होली के दिन गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दुसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर इस त्योहार को मनाते हैं।

एक अन्य कथा के अनुसार देवों और दानवों में इसी दिन वर्तमान मध्यप्रदेश के मराकस कस्बे में एक वार्ता हुई और दोनों ने आगे से शत्रुता भुला कर मित्रता से रहने का निर्णय लिया। इसके बाद देवों और दानवों ने खुशी में राख और धूल से एक दुसरे को सराबोर करके खुशियां मनाईं और तब से होली मनाने की परंपरा शुरू हो गयी।

क्या 5जी आने से मौसम की भविष्यवाणी पर होगा असर!

एजेंसियां :हाल में जब सबीने तूफान आया तो उसकी सटीक भविष्यवाणी समय रहते आ गई थी. मौसमविज्ञानियों को डर है कि 5जी आने के बाद उनको मुश्किल हो सकती है. टेलिफोन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहों को बाधा डालती है.मौसम की भविष्यवाणी आजकल इतनी सटीक हो गई है, जितनी पहले कभी नहीं थी. इसकी वजह धरती पर नजर रखने वाले सैटेलाइट हैं जो पूरी दुनिया में मौसम के लिए जरूरी सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं. उसके बाद ये सूचनाएं मौसम की भविष्यवाणी करने वाले कंप्यूटरों में पहुंचती हैं.जिन सूचनाओं के आधार पर आने वाले मौसम का पता चलता है उनमें से एक वातावरण में भाप की मात्रा है. ये अदृश्य पानी है जो भाप बनकर गैस के रूप में वातावरण में मौजूद रहता है. ये ठंडा होने पर पहले बादल बनता है और फिर वर्षा का कारण बनता है.यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिकी नासा के उपग्रह इसे मापते रहते हैं. भारत सहित दूसरे देशों ने भी मौसम की जानकारी हासिल करने के लिए अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं. मौसमविज्ञानियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भाप को देखने लायक बना सकें. यदि उन्हें उसकी मात्रा का पता है तो ठीक ठीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कब और कहां तूफान या चक्रवात आने वाला है.बाढ़ और गर्म हवाओं का बढ़ा प्रकोप जेनेवा स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा पृथ्वी की जलवायु का वार्षिक मूल्यांकन किया गया. इसमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उद्देश्य से 2015 के पेरिस समझौते की मुख्य बातों को रेखांकित किया गया. डब्ल्यूएमओ सेक्रेट्री जनरल पेटेरी टालस ने कहा, "पहले सैकड़ों सालों में एक बार बाढ़ या गर्म हवाएं चलने जैसी बात होती थी लेकिन अब यह अकसर हो रहा है.यदि उन्हें भाप की मात्रा का ठीक से पता नहीं चलता है तो भविष्यवाणी की जगह 100 किलोमीटर दूर तक हो सकती है. चेतावनी का अनुमानित समय भी गलत हो सकता है जिसकी वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

ब्रिटेन की एक स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का असर विमानों की उड़ान पर भी होगा. विमानों को आकाश में अधिक हलचल (टर्ब्युलेंस) का सामना करना होगा. इसमें तकरीबन 149 फीसदी की वृद्धि होगी.प्रो. जिम्मर को डर है कि तब तक मौसमविज्ञानियों के लिए बहुत देर हो जाएगी।

हिमाचल में कृषि से दूर हो रहे हैं किसान

कृषि लागत में हो रही वृद्धि और जंगली जानवरों की समस्या के चलते हिमाचल का किसान खेती से दूर होता जा रहा है। हिमाचल के वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राज्य की जीडीपी में कृषि-बागवानी एवं संबंद्ध क्षेत्रों का 12.73 प्रतिशत होने का दावा किया गया है। जो कि पिछले दो दशकों में एक चौथाई घट गया है।वर्ष 2000 में सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि-बागवानी एवं संबंद्ध क्षेत्रों का जीडीपी में 46 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, वर्ष 2014-15 में घटकर 15.35 और इस साल केवल 12.73 प्रतिशत तक सिमट कर रह गई है।

हरियाणा की महिलायें भी हैं कुपोषित

देशा में देश हरियाणा, जित दूध-दही का खाणा यह देसी कहावत भले ही यहां के पुरुषों पर फिट बैठती हो, पर आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा की लड़कियों और महिलाओं की स्थिति किसी दूसरे पिछड़े प्रदेश से अच्छी नहीं है। इस प्रदेश की 40 प्रतिशत लड़कियों का वजन उम्र और कद, काठी के लिहाज से कम है और करीब 60 प्रतिशत महिलाएं अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। प्लान इंडिया नामक एक संस्थान ने हाल में एक सर्वे कर डेटा इकट्ठा किया था। इसके मुताबिक, हरियाणा की 40 प्रतिशत लड़कियों का वज़न कम पाया गया और 60 फीसदी महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त मिलीं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि खान, पान पर विशेष ध्यान नहीं देने, प्रदूषण और बदलती जीवन शैली के कारण महिलाएं खून की कमी और लड़कियां कम वजन का शिकार हो रही हैं। विश्व महिला दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर गुरुग्राम की महिला कॉलेज से प्रदेश स्तरीय पोषण अभियान शुरू करेंगे। अभियान के तहत प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों को खान, पान को लेकर सजग करने के अलावा उन्हें ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।

पाइलकोट झारखण्ड और देश कर एतिहासिक महत्व वाला ठांव हय

बलदेव शर्मा

गुमला से 25 किलोमीटर पूरबे पाइलकोट हय । जे कभी नागवंशी राजा मन कर राजधानी रहे । पाइलकोट के आइज काइल पालकोट भी कहल जाएला। मान्यता हय कि पाइलकोट कर पुराना नाम पंपापुर रहे। ओहे पंपापुर जेकर संबंध में महाकवि तुलसीदास जी आपन लिखल रामचरितमानस कर किष्किंधाकाण्ड में ऋष्यमुक पर्वत कर बरनन कइर हयं। यानि पाइलकोट झारखण्ड और देश कर एतिहासिक महत्व वाला ठांव हय । काहे कि पंपापुर कर ऋष्यमुक पर्वत में ही महाबली बाली कर भाई सुग्रीव छुईप के रहत रहलयं।

सुग्रीव कर ऋष्यमुक पर्वत में छुईप के रहेक कर कारण पर्वत में अंझखंज खोह आउर शापित रहे। सेहे लागिन बाली उहां नी जात रहे आउर उहां अनाड़ी जवईया के कोई छुइप जायहे तो खोईज पावेक कठिन ही नहीं असंभव बताल जायला। राउरे अचरज करब पाइलकोट कर पहाड़ में भी सात पाटैइन खोह आहे। कभी राउरे जाय के अंदाज कईर सकीला कभी जायही तो देइख होवब। अइसे तो इहां कर खोह कर बारे में सही सही एखनो कोई नी बताय पारी।मुदा शीतलपुर मलमलपुर खोह कर उपरे आउर नीचे तीन तीन पाटैइन आहे कहर जायला।काहे कि जे बेरा राजा राधेश्याम नाथ साहदेव जीयत रहयं से बेरा गुमला टीचर्स ट्रेनिंग कालेज कर प्रिंसिपल लाल साहेब आउर कुछ मास्टर मनकर संगे हम भी पहाड़ के देखेक जाय रही। से बेरा राधेश्याम जी बड़का टोर्च लेइग के हमरे मनके देखाय रहयं । सेहे ले हम विश्वास करीला। राधेश्याम जी हमरे मनके बताय रहयं कि माता दशभुजी कर मंदिर से उनकर निवास तक कैसे सुरंग जुड़ल रहे। एखनो हम । मुदा मरम्मईत कर अभाव में एखन बंद करली जायहे। कोई संकट या दुश्मन मनकर हमला होवल से बेरा सुरंग से पहाड़ में चईढ़ के गोला-बारूद करत रहयं। सेहे लागिन पालकोटके कोई हराएक नी पाइर रहयं। कयबार औरंगजेब भी कोशिश कइर रहे लेकिन हराएक नी पारलक।

कहयंना आखिरकार औरंगजेब पालकोट कर राजा के ताम्रलेख भेईज के सम्मान देइ रहे आउर आगे पाइरकोट पर कभी हमला नी करेक कर वचन देइ रहे। हम मुद्दा से भटकत्थी लेखे लागत्थे । चलु घुरीला । मुदा इबात के भी बाताएक जरूरी रहे। हम पाइलकोट पहाड़ यानि ऋष्यमुक पर्वत कर बात करत रहली। जे पहाड़ उपरे तालाब आउर जंगल हय। उकर नीचे सात तल्ला गुफा। जल्दी कोनो अदमीन के विश्वास नी होवी। क्रमशः..

कोर्ट ने कहा, फलों को पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किसी को जहर देने के समान

एजेंसियां

फलों को पकाने के लिए कीटनाशकों व रसायनों का प्रयोग उपभोक्ताओं को जहर देने के समान है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई से ही यह रुकेगा। यह तल्ख टिप्पणी अदालत ने फल व सब्जियों में कीटनाशकों के प्रयोग पर निगरानी से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। आम को पकाने के लिए कैल्शियम कारबाइड का प्रयोग किसी को जहर देने के समान है तो ऐसे लोगों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा क्यों नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को दो दिन के लिए भी जेल भेजा जाता है तो उसका भी काफी असर होगा। इस जनहित याचिका की शुरुआत कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए की थी।

न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व एजे भंबानी की खंडपीठ ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या अब भी आम को पकाने के लिए अब भी कैल्शियम कारबाइड का इस्तेमाल हो रहा है? कोर्ट ने अथोरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अगली तारीख पर मौजूद रहने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कृषि मंत्रालय से भी पूछा है कि क्या कोई ऐसी किट है जिससे उपभोक्ता खुद घर पर फलों में कैल्शियम कारबाइड का पता लगा सके।

मंत्रालय ने बताया कि ऐसी कोई किट उपलब्ध नहीं है और कैल्शियम कारबाइड की जांच केवल प्रयोगशाला में की जा सकती है। दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता नौशाद अहमद खान ने कोर्ट को बताया कि संबंधित विभाग जांच के लिए बाजारों से फलों के सैंपल लेता है और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाता है। कुछ सैंपलों की जांच में रसायन नहीं पाया गया है और बाकी सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कोर्ट खुद शुरू की गई जनहित याचिका के साथ ही दो अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है जिनमें खाद्य पदार्थों विशेषकर कृषि उत्पादों पर कीटनाशकों व रसायनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र राजुल जैन ने कुछ समय पहले रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि फलों व सब्जियों में कीटनाशकों व रसायनों के अधिक प्रयोग के कारण कई देशों ने इनका आयात बंद कर दिया है और कई देश इस पर विचार कर रहे हैं।

नदी घाटी के शहरों के लिए चुनार बन सकता है रोल मॉडल?

एजेंसियां : गंगा नदी घाटी में बसे शहरों के लिए मल मूत्र से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है, इसके लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या ये कारगर साबित होंगे?

शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला मानव मल मूत्र का दूषित पानी गंगा सहित देश में नदियों के प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। समस्या की जड़ यह है कि भारत के शहरों में मलमूत्र के उत्सर्जन का सही ढंग से प्रबंध नहीं किया जाता है। जो जल प्रदूषण तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही, स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। पहले और बाद में चलाए गए लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में ज्यादातर का फोकस शौचालय निर्माण, सीवरेज नेटवर्क और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर रहा है। दो अक्टूबर 2019 में भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया। हालांकि यह दावा सही है या नहीं, लेकिन यह सही है कि देश में 10 करोड़ शौचालय बने हैं। यह देखते हुए कि देश में केवल 28% आबादी सीवरेज सिस्टम (2011 की जनगणना) से जुड़ी थी, इन शौचालयों का अधिकांश हिस्सा सेप्टिक टैंक जैसी ऑनसाइट सफाई व्यवस्था से जुड़ा होगा। इन शौचालयों से निकलने वाला कचरा नदियों-नालों को प्रदूषित करता रहेगा और मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ाएगा। लेकिन हम अपनी नदियों और जल निकायों को प्रदूषित करना जारी नहीं रख सकते हैं, जो हमारे पीने के पानी का एक बड़ा स्रोत भी है।सीवरेज सिस्टम के न होने के कारण मल मूत्र के कीचड़ को सुरक्षित तरीके से प्रबंधन की जरूरत है। इसमें से एक नीति को एफएसएसएम कहा जाता है, जिसमें शौचालय के साथ ही मल मूत्र के कीचड़ को इकट्ठा किया जाता है और उसे फिर ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) तक पहुंचाया जाता है। इस संबंध में 2017 में एक राष्ट्रीय नीति भी अधिसूचित की गई है। कई राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में एफएसएसएम नीति लागू है। लेह, सिन्नर, वाई, नरसापुर, वारांगल, देवनहाली (कर्नाटक) में पॉयलट एफएसटीपी बनाए गए हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अमृत मिशन के तहत बने हैं और एफएसएसएम को एक कंपोनेंट के तौर पर फंडिंग भी की जा रही है। पिछले 4 वर्षों के दौरान इस तथ्य को मान लिया गया है कि शहरी भारत के सभी घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। एक पूरे शहर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ना एक थकाऊ काम है, क्योंकि इसके लिए न केवल शहर की पूरी सड़कों को खोदने की जरूरत होती है,

बल्कि सभी घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने की भी जरूरत होती है। चूंकि हमारी घनी आबादी वाली बस्तियों की गलियां संकीर्ण हैं और अनियोजित हैं।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में ओडिशा के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने माना कि एक शहर में सीवरेज नेटवर्क बिछाना ओपन हार्ट सर्जरी करने के बराबर जोखिम भरा है। हमें अपशिष्ट जल और जल निकासी का प्रबंधन करने के लिए वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) में भी एफएसएसएम की आवश्यकता को मान लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनार शहर में एक एफएसटीपी के लिए फंड की स्वीकृति दी गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनएमसीजी ने सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है।यह परियोजना अद्वितीय है, क्योंकि इसमें स्वच्छता के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। जैसे, सेप्टिक टैंक खाली करना, ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली का ब्यौरा, सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग, वेब आधारित एमआईएस आदि। इस-के अलावा यहां से निकलने वाली साफ पानी का इस्तेमाल वृक्षारोपण जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा।

इस ट्रीटमेंट प्लांट के चालू होने तक एक अंतरिम व्यवस्था की गई है, जिसमें शहर के जल स्रोतों और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना मल कीचड़ को सुरक्षित रूप से निपटाने का इंतजाम किया गया है। कई राज्य अपने शहरी क्षेत्रों में एफएसटीपी बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा राज्य इसका नेतृत्व कर रहा है। यहां अमृत फंडिंग के माध्यम से 10 एफएसटीपी बन चुके हैं और 26 एफएसटीपी के निविदा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर हम गंगा बेसिन को देखें, तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही झाँसी में एक एफएसटीपी है, जिसे नगर निगम की पहल पर बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश जल निगम को अमृत फंडिंग के माध्यम से राज्य में एफएसटीपी की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में उन्नाव में एक एफएसटीपी परीक्षण चरण के तहत लगा है। लोनी, रायबरेली और लखीमपुर में एफएसटीपी के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। अन्य 52 शहरों के लिए एफएसटीपी की योजना बनाई गई है, जिसमें से 6 शहरों के लिए निविदाएं पहले से ही जारी की चुकी हैं।चुनौतियां अभी भी शेष हैं।हालांकि एफएसटीपी बनने से कुछ समाधान हो जाएगा, लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि सेप्टिक टैंक सही ढ़ंग से बने हैं या नहीं। उनमें बीआ-ईएस कोड का पालन हो रहा है या नहीं। इन सेप्टिक टैंकों को नियमित रूप से खाली करने की जरूरत होती है। यदि 2 से 3 साल के बीच इन्हें खाली नहीं किया गया तो ये प्रदूषण फैला सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा एफएसएसएम में किचन या बाथरूम से निकलने वाले गंदे पानी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से मच्छर पनपते हैं। ऐसे में, इन्हें सीवर से जुड़ने जैसे समाधान उपलब्ध है। शहरी स्वच्छता और नदी प्रदूषण को कम करने के लिए एक समग्र नीति के साथ-साथ गंगा बेसिन के लिए ठोस दिशानिर्देश और उन्हें लागू करने की भी सख्त जरूरत है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।